की गई है ताकि मध्यम और लघु सिंचाई तथा मृदा संरक्षण परियोजना के लिये ऋण मुहैया किया जा सके। त्वरित सिंचाई विकास कार्यक्रम की एक योजना भी शुरू की गई है ताकि चुनिंदा बड़ी और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा किये जाने के लिये ऋणों के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान की जा सके।

विवरण

कृषि में सकल पूंजी निर्माण

(अखिल भारत)

(करोड़ रुपये)

वर्ष	वर्तमान मूल्यों पर	1980-81 मूल्यों पर
1	2	3
1980-81	4636	4636
1931-82	5107	4503
1982-83	5734	4590
1983-84	5620	4101
1984-85	6475	4549
1985-86	7016	4325
1986-87	7045	4011
1987-88	8389	4414
198S-89	9063	4346
1989-90	10025	4353
1990-91	11592	4594
1991-92	13390	4729
1992-93	16614	5372
1993-94	17009	5038
1994-95	20737	5678
1995-96*	24937	6301

* = सरसरी तौर पर लगाए गए अनुमान ।

Report of the NHRC on Starvation Deaths in Orissa

4432. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the National Human Rights Commission (NHRC) has submitted its report regarding starvation deaths in Orissa; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Supply of Subsidies Fcrtiliezers to Orissa

4433. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the amount of subsidised fertilizers demanded and supplied to the

state of Orissa during the last three years;

(b) the reasons for the short supply; and

(c) the steps taken by government in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (c) Urea is the only fertilizer which is under statutory price control and for which allocation is made at present. All phosphatic and potassic fertilizers stand decontrolled with effect from 25.8.1992. Ammonium Sulphate, Ammonium Chloride and Calcium Ammonium Nitrate were also under price control from 25.8.1992 to 9.6.1994. The table below gives the assessed requirement, supply and consumption of urea in Orissa during the years 1994-95, 1995-96 and 1996-97:

(Lakh tonnes)

	Assessed Requirement	Supply*	Consumption
1994-95	3.00	2.85	2.76
1995-96	3.30	3.83	3.12
1996-97	4.79	4.53	3.91 (Estimated)

*Excluding stock with State Institutional agencies.

The availability of urea in Orissa during the last three years was, by and large, satisfactory. When ever pockets of shortages were reported by the State Government, corrective measures by way of rushing urea through alternative sources were taker! to over come such stituations. Periodical meetings to review sales and availability of urea are also held to take corrective measures.

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापार निति को तर्क-संगत बनाया जाना।

4434. **श्री राधाकिशन मालवीयः**

श्री अजीत जोगी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि निर्यात को बढ़ावा देने, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने, विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अपनी व्यापार नीति को तर्क संगत बनाया है;

(क) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ख) सरकार ने कृषि के निर्यात के लिए सुविधाएं उपलध कराने हेतु क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) कृषि निर्यात को और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए नीतियों में काफी बदलाव किए गए हैं। महत्वपूर्ण वस्तुओं विशेषरूप से खद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आवश्यक ग्रीनहाउस उपस्कर तथा पौधों और मशीनरी पर आयात शुल्क कम करने तथा निर्यात के लिए ऋण की सुलभता से कृषि निर्यात को बढ़ावा मिला है। कृषि निर्यातों पर लगने वाले अधिकतर प्रतिबंदों को हटा लिया गया है। प्रतिबंधित सूची में कृषि से संबंधित वस्तुएं काफी मात्रा में कम कर दी गई हैं तथा बहुत कम वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर लाइसेसिंग या मात्रात्मक प्रतिबंध लागू होता है।

आदानों व पैदावार हेतु नूनतम समर्थ्न मूल्यों पर मिलने वाली सब्सिडी किसान के लिए रक्षा कवच का काम करती है, जब कि उपभोक्ताओं के